क्योंकि यह हम यहा बहस में नही ले जा सकते ?

श्री चन्द्रशेखर : अध्यक्ष महोदय, यह पूछने की जरूरत नही है । जो लोग सरकार मे हो उस आंदोलन से उनकी सहानुभूति हो सकती है। उन्होंने जो खर्च किया है, इतनी बुद्धि उनको है कि वह सरकारी पैसे से खर्चा नहीं हुआ होगा चन्दा मागकर खर्च किया होगा।

*166 *(The questioners (Shri Shiv Pratap Mishra and Shrimti Suryakanta Patil) were absent. For answer vide Col. 8 35-37 infra).*

*167. *(The questioners (Shri Ghufran Azam) was absent for answer vide Col.. 37 infr].*

*168. *[The questioner (Dr. Bapu Kaldate) was absent for answer vide Cols. 38-39 infra.)*

ब्रह्मपुत्र घाटी मे अभियान के लिए जापान के व्यावसायिक दलों की अनुमति

*169. श्री प्रभात कुमार सामन्तराय : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार जापान के कतिपय व्यावसायिक दलो को रक्षा मत्रालय और इडियन माउन्टेनियरिंग फाउन्डेशन के सहयोग से महत्वपूर्ण ब्रह्मपुत्र घाटी मे अभियान चलाने के लिए अनुमति देने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हा, तो उसके क्या कारण है ; और

(ग) क्या ऐसी अनुमति देने में देश की सुरक्षा का सवाल जुडा हुआ है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) (क) रक्षा मंत्रालय की सहमति से गृह मंत्रालय ने भारत जापान ब्रहमपुत्र अभियान को अनुमोदित कर दिया था अनुज्ञा के अनुमोदन का मुख्य विचार यह था कि इस अभियान का नेतृत्व भारत तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा किया जा रहा है।

(ख) और (ग) भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस जो भारत तिब्बत सीमा की सुरक्षा के लिए गठित विशेष बल है को शामिल करने के आधार पर आईएम एफ जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रायोजित एजेसी है, को अनुमति दी गई। सुरक्षा के पहलुओ पर विचार किया गया और उचित ध्यान दिया गया है।

SHRI PRAVAT KUMAR SAMANTARAY : The Brahmaputra Valley is a very sensitive area. I do not know why the Government has given permission to this expedition with the Japanese who are in possession of very sensitive electronic photographic equipments. Moving in the name of expedition, they are expected to have maps which we do not possess in India but which are available in foreign countries So I would like to know from the honourable Minister whether all these aspects were considered before giving permission to such an expedition ?

MR. CHAIRMAN : Question Hour is over.

WRITTEN ANSWER TO QUESTIONS

Import of Components/kits by M/s. Maruti Udyog Ltd.

*163 SHRI MAHENDRA PRASAD : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item which appeared in the Indian Express dated the 5th October, 1990 to the effect that the Maruti Udyog Limited had imported components and Kits worth crores of rupees from the Japanese Suzuki unit, which were of no use to the

Japanese giant and of little value to India ; and

(b) if so, the estimated value of these components, which are now proposed to be scrapped; and how many of them have since been utilised ?

THE MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (SHRI KAMAL MORARKA) : (a) and (b) The news item had come to the notice of the Government Shortly before the production of the old model of the Maruti 800 cc car ended, it was found that it was not possible to produce cars froem 765 of the already imported CKD kits because some of their components had been damaged etc. It was also found that there were some extra parts available through salvaging from damaged cars which could be converted into an additional 99 cars if some balancing parts were imported. Accordingly, 864 kits smaller than the normal CKD kit were imported and their value was US$ 7,78,800.96 (Rs. 94,74,464). 864 cars were, thus, produced and sold. However, all the imported components could not be made use of as the import of components had to be done in the form of kits, while the requirement of different parts for balancing the CKD kits was not the same. Thus, components worth Rs. 22,96,849/- were utilised and the remaining were transferred to the Spare Parts Department. Scrapping of spare parts is taken up as and when they become obsolete and unserviceable.

प्रशासनिक सेवा (प्रारम्भिक) के प्रश्न-पत्र का लीक किया जाना

*166. **श्री शिव प्रताप मिश्र :**

श्रीमती सुर्यकान्त पाटील :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गत वर्ष की प्रशासनिक सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा के प्रश्न-पत्र विभिन्न केन्द्रो पर, विशेषतया पटना में, लीक कर दिये गये थे ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान इस संबंध में 9 दिसम्बर, 1990 के "टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित समाचार की ओर भी दिलाया गया है ;

(ग) क्या इस सबध मे कोई जाच की गई है; यदि हा, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) लीक के लिए जिम्मेदार अधिकारियो/कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ङ) यदि उपरोक्त भाग (घ) का उत्तर "ना" हो, तो तत्संबंधी कारण क्या है तथा ऐसी घटनाये भविष्य में न हो इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उटाने का विचार रखती है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) से (ङ) सरकार का ध्यान दिनाक 9 दिसम्बर, 1990 के "टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित रिपोर्ट की ओर दिलाया गया था जिसमें 10 जून, 1990 को ली गई सिविल सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा के प्रश्न-पत्र के लीक होने का आरोप लगाया गया था । सरकार के अनुरोध पर, सघ लोक सेवा आयोग, जो प्रशासनिक सेवा परीक्षा आयोजित करता है, ने विस्तृत जांच की और यह निष्कर्ष निकाला कि प्रश्न-पत्रों के लीक होने संबंधी आरोप निराधार था ।

2. सिविल सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा को चुनौती देने के संबंध मे केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष दायर किए गए आवेदन-पत्रों की विषय-वस्तु में भी प्रश्न-पत्रों के लीक होने का आरोप लगाया गया था । केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, इलाहाबाद न्यायपीठ ने इसकी जांच की और अपने दिनांक 14 दिसम्बर, 1990 के आदेश में यह निर्णय दिया कि प्रथम-दृष्टया इस निर्णय पर पहुंचना कठिन है कि प्रश्न-पत्र लीक हो गए थे ।